प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष
एंव
निर्भीक

साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक – 16 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 18 – 25 अप्रैल 2016 मूल्य पांच रूपए

क्या प्रदेश वित्तिय आपात स्थिति की ओर बढ़ रहा है?

शिमला/शैल। किसी भी सरकार की आर्थिक एवं वित्तिय स्थिति का सही आकलन करने की संवैधानिक जिम्मेदारी राज्यों में तैनात महालेखाकार कार्यालय की रहती है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किया गया लेखा जोखा हर वर्ष राज्य की विधानसभा में रखा जाता है। सदन में इस लेखे के आने के बाद विधानसभा की पब्लिक एकाऊंटस कमेटी महालेखाकार की रिपोर्ट में दर्ज टिप्पणीयों पर विस्तृत चर्चा करती है और संबंधित विभागो के सचिवों एवम् अन्य शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में जवाब तलबी करती है। सी ए जी की रिपोर्ट में दर्ज टिप्पणीयों को हल्के से लेना कई बार राज्य सरकारों को भारी भी पड़ जाता है। सरकार एक तय वित्तिय अनुशासन और प्रबन्धन के मानदण्डों का उल्लंघन ना करे इसकी पूरी तस्वीर कैग रिपोर्ट में दर्ज रहती है। वित्तिय अनुशासन के लिए ही वर्ष 2005 में एफआर बी एम एक्ट लाया गया था जिसमें 2011 में संशोधन भी किया गया था। एक्ट के अतिरिक्त इस बजट में मैन्यूअल भी है। लेकिन क्या इन सबकी अनुपालना की जा रही है? कैग में सरकार के आर्थिक और वित्तिय प्रबन्धन को लेकर गम्भीर सवाल उठाए गए हैं बल्कि कैग की टिप्पणीयां सदन की पी ए सी को भी कठघरे में खड़ा करती हैं।

वर्ष 2014-15 की सदन में आई कैग रिपोर्ट में कहा गया है As per Article 204 (3) of the Constitution of India, no money shall be withdrawn from Consolidated Fund of the State except under appropriation made by law passed in accordance with the provision of this article .

Notwithstanding the above, excess expenditure over budget provision increased from रू 474.86 crore in 2013-14 to rupees 1,585.69 crore in 2014-15.

As per Article 205 of the Constitution of India, it is mandatory for a state Government to get the excess over a grant/appropriation regularized by the state Legislature. Although no timelimit for regularisation of expenditure has been prescribed under the Article, the regularization of excess expenditure is done after the completion of discussion of the appropriation Account by the Public Accounts Committee (PAC). However, the excess expenditure amounting to rupees 5,055.89 crore **(Appendix 2.2)** for the years 2009-10 to 2013-14 was yet to be regularized as of september 2015. सदन की बैठकें वर्ष में तीन बार होती हैं ऐसे में वर्ष 2009-10 में समेकित निधि से किये गये अधिक खर्च का अब तक नियमितिकरण न होना सारे वित्तिय प्रबंधन की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े करता है। क्योंकि बजट प्रावधानो से लगातार अधिक खर्च करना कुछ विभागों का स्वभाव ही बन गया है। प्रदेश के सिंचाई एवम् जन स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2010-11 में 586.72 करोड़ वर्ष 2011-12 में 350.71 करोड़ वर्ष 2012-13 में 285.21 करोड़ वर्ष 2013-14 में 255.33 करोड़ तथा वर्ष 2014-15 में 474.07 करोड़ बजट प्रावधानो से अधिक खर्च करके संविधान की धारा 204 का सीधा उल्लंघन किया है। लेकिन बजट प्रावधानों से हर वर्ष ज्यादा खर्च करने के बावजूद राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार कम होती जा रही है। 2010-11 में यह वृद्धि दर 18.24 %, 2011-12 में 16.62 %, 2012-13 में 14.76%, 2013-14 में 12.57 % तथा 2014-15 में यह केवल 11.35 % रह गई है।

प्रदेश के जी एस डी पी वृद्धि में जहां लगातार कमी आ रही है वहीं पर प्रदेश का कर्ज भार हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2010-11 में यह कर्ज 26415 करोड़ था, वर्ष 2011-12 में 28228, 2012-13 में 30442, 2013-14 में 33884 और 2014-15 में यह बढ़कर 38192 करोड़ हो गया है। जिस अनुपात में यह कर्जभार बढ़ रही है उस पर कैग में गम्भीर सवाल उठाए गए हैं आज कर्ज लौटाने के लिए सरकार को और कर्ज लेना पड़ रहा है। दूसरी और प्रशासन इस वित्तिय स्थिति को कितनी गम्भीरता से ले रहा है इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि कई विभाग बजट का अधिकांश धन वर्ष के अंतिम मास मार्च में खर्च कर रहे हैं।

ऊर्जा के लिये 2014-15 में 403.78 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसमें मार्च 2015 में विभाग ने 330 करोड़ (82%) खर्च किये हाऊसिंग के लिये 16.52 के कुल प्रावधान में से मार्च में 11.05 करोड़ खर्च किये गये (67%) मध्यम सिंचाई के लिये 22.91 करोड़ में से 22.81 करोड़ (99%) मार्च में खर्च किये गये, कमांड एरिया विकास के 18.74 करोड़ में से 15.29 (82%)मार्च में खर्च हुए और सड़क एवं पुल 21.49 करोड़ में से 16.08 (75%) मार्च में खर्च होना इन विभागों की नीयत और कार्यशैली को कठघरे में ला खड़ा करता है।

- GSDP का 40% और राजस्व प्राप्तियों से 214% अधिक हुआ कुल कर्जभार
- FRBM और बजट मैन्यूअल मानकों की नजरअन्दाजी
- संविधान की धारा 204 और 205 की अवमानना
- राजभवन और विधानसभा भी बजट प्रावधानों से अधिक खर्च करने वालों में शामिल
- सवालों में वित्त मंत्री और वित सचिव

2014-15 में इन विभागों में हुआ प्रावधानों से अधिक खर्च

संविधान की धारा 204 का उल्लंघन करके बजट प्रावधानों से अधिक खर्च करने वालों में प्रदेश के 16 विभाग शामिल हैं। इनमें राज्यपाल एवं मन्त्री परिषद आबकारी एवं कराधान, कृषि, बागवानी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊर्जा विकास, विधानसभा, लोकनिर्माण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वित्त, जनजाति विकास और उद्योग विभाग तथा सूचना प्राद्यौगिकी आदि विभाग शामिल है। इनमें राजस्व से लेकर केपिटल एकाऊंट तक में प्रावधानों से अधिक खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के 42642 उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं हो पाये हैं। इस तरह वित्तिय प्रबंधन के सारे मानदण्डो पर सरकार लगातार असफल सिद्ध हो रही है। इन मानदण्ड़ो के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्व धारा शून्य पर लाया जाना था। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो सका है। आज प्रदेश का कर्जभार राजस्व प्राप्तियां का 214 % और सकल घरेलू उत्पाद का 40% हो चुका है और यह एक अच्छा संकेत नहीं है।

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखें उद्यमी–राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उद्योग जगत का आह्वान किया है कि वे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखें ताकि हिमाचल के प्रदूषण रहित वातावरण को अक्षुण्ण रखा जा सके।

राज्यपाल सोलन जिले के नालागढ़ उपमण्डल के बद्दी में औद्योगिक इकाई 'मार्केटिंग हाऊस यूनिट-2' का शुभारम्भ करने के उपरान्त उपस्थित उद्यमियों को सम्बोधित कर रहे थे।

1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस लघु उद्योग में 25 परिवारों को प्रत्यक्ष तथा लगभग 150 परिवारों को अप्रत्यक्ष रोज़गार उपलब्ध होगा। यहां सोया बड़ी, सोया चूरा, मैकरोनी, पास्ता, मक्की आटा, गेहूं का दलिया, गेहूं आटा तथा पशु चारा जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल का स्वच्छ वातावरण विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रदूषण रहित वातावरण को लम्बे समय तक यथावत बनाए रखने के लिए उद्यमियों को अपने उत्तरदायित्व का उचित निर्वहन सुनिश्चित बनाना होगा। प्रदेश का निर्मल वातावरण जहां बेहतर उत्पादन बनाए रखने में सक्षम है वहीं इसके माध्यम से उद्योगों को स्थाई रखने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्यमी औद्योगिक क्षेत्र को हरा-भरा बनाए रखें तथा औद्योगिक कचरे के निपटारे के लिए दीर्घकालिक नीति बनाएं।

राज्यपाल ने कहा कि कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अन्तर्गत उद्यमी समूचे क्षेत्र में अनेक विकासात्मक कार्यों में सहयोग दे सकते हैं। उन्होंने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत कार्य करने के लिए क्षेत्र के उद्यमियों को बधाई दी। उन्होंने मार्केटिंग हाऊस यूनिट-2 द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत बद्ददी में 51 डस्टबिन उपलब्ध करवाए जाने का भी स्वागत किया।

राज्यपाल ने इकाई का दौरा कर तैयार किए जा रहे उत्पादों की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। मार्केटिंग हाऊस यूनिट-2 के प्रबन्ध निदेशक सुरेश बंसल ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए इकाई द्वारा तैयार किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ऐसी 20 इकाईयां स्थापित की जाएंगी।

नगर निगम धर्मशाला के महापौर को एंबर लाईट

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निगम धर्मशाला के महापौर को उनके अधिकार क्षेत्र में कार्यालय वाहन पर फलैशर सहित एंबर लाईट इस्तेमाल करने की स्वीकृति प्रदान की है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

10वां सिविल सेवा दिवस हिप्पा में आयोजित किया जाएगा

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि 10वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह 21 अप्रैल, 2016 को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलॉन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म' होगा।

उन्होंने कहा कि सिविल सेवा दिवस के अवसर पर जिला, खंड तथा स्थानीय निकायों स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक- जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार- ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

प्रदेशवासियों को महावीर जयन्ती पर बधाई

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेशवासियों को महावीर जयंती के अवसर पर बधाई दी है।

राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि भगवान महावीर का अंहिसा का संदेश हमारे जीवन और समाज में शांति और भाईचारा बढ़ाने की दिशा मैं महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महावीर की शिक्षाएं हमारी वाणी और व्यवहार में सच्चाई का मार्ग दर्शाते हुए हमें सादा एवं स्वच्छ जीवन जीने के लिये प्रेरित करती हैं।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने संदेश में विशेषकर जैन बन्धुओं को बधाई देते हुए कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाओं, आदर्शों एवं सिद्धान्तों का अनुसरण करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर द्वारा दिखवाया गया मार्ग हमें सच्चा जीवन जीने के लिये प्रेरित करता हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर शांति, अंहिसा व आपसी सौहार्द्ध के अग्रदूत थे और हमें उनके दर्शाए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Jaisinghpur Division H.P. PWD, Jaisinghpur on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the following works from the approved and eligible contractors /firms enlisted in HP PWD, (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the HP General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before 09.05.2015 up to 10:30 AM. And the same shall be opened on the same day at 11:00 AM in the presence 0f intending contactors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (Non-Refundable) up to 07.05.2016 upto 4:00 PM and the application for issue of tender form shall be received up 06.05.2016 upto 12:00 noon. The Earnest Money in the shape of NSC/Time deposit account /saving account of the post office in HP duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender . conditional /incomplete tender & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reason.

Sr. No. Name of work	Estimated Cost Rs	Earnest Money	Time	Form No	Cost of Form
1. Annual surfacing of Maryana to KUD road km 1/0 to 2/0 (DRRP No HP0401 VR007457102 (Rural Road)	5,75,170/-	11,600/-	One Month	6&8	350/-
2. Annual surfacing of Maryana to KUD road km 2/0 to 3/0 (DRRP No HP0401 VR007457103 (Rural Road)	5,75,170/-	11,600/-	One Month	6&8	350/-
3. Annual surfacing of Maryana to KUD road km 3/0 to 4/0 (DRRP No HP0401 VR007457104 (Rural Road)	5,75,170/-	11,600/-	One Month	6&8	350/-
4. Annual surfacing of Tramblu to KUD road km 3/0 to4 /0 (DRRP No HP0401 VR00006257104 (Rural Road)	5,75,170/-	11,600/-	One Month	6&8	350/-
5. Annual surfacing of Tramblu to KUD road km 4/0 to 5/0 (DRRP No HP0401 VR00006257105 (Rural Road)	5,75,170/-	11,600/-	One Month	6&8	350/-
6.Annual surfacing of Tramblu to KUD road km 5/0 to 6/0 (DRRP No HP0401 VR00006257106 (Rural Road)	5,75,170/-	11,600/-	One Month	6&8	350/-
7. Annual surfacing of Surfacing of Majheen Nahallian Vai Pian-Da- Ghatta road km 3/0 to 4/0 (DRRP No HP0401 VR006657104 (Rural Road)	5,75,170/-	11,600/-	One Month	6&8	350/-
8.Annual surfacing of Surfacing of Majheen Nahallian Vai Pian-Da- Ghatta road km 4/0 to 5/0 (DRRP No HP0401 VR006657105 (Rural Road)	5,75,170/-	11,600/-	One Month	6&8	350/-
9. Annual surfacing of Surfacing of Majheen Nahallian Vai Pian-Da- Ghatta road km 5/0 to 5/750 (DRRP No HP0401 VR006657106)	4,31,844/-	8,700/-	One Month	6&8	350/-
10. Annual Surfacing of Oach Pihri road km 2/0 to 3/0 (Rural Road) (DRRPNO. HP0401VR 0045571103)	6,41,265/-	12,900/-	One Month	6&8	350/-
11. Annual Surfacing of Oach Pihri road km 3/0 to 4/0 (Rural Road) (DRRPNO. HP0401VR 0045571104)	6,41,265/-	12,900/-	One Month	6&8	350/-
12.Annual Surfacing of Oach Pihri road km 4/0 to 5/0 (Rural Road) (DRRPNO. HP0401VR 0045571105)	6,41,265/-	12,900/-	One Month	6&8	350/-
13. C/o Division office building HP PWD Division Jaisinghpur (SH:- C/O boundary wall RD 0/0 to 0/100)	5,21,498/-	10,500/-	Two Month	6&8	350/-

Terms & Conditions:-
The tender form and other detailed conditions can be obtained from the website of the Department or office of the Executive Engineer, Jaisinghpur Division HP PWD Jaisinghpur upto date specified above

Adv. No.-0145/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER
NOTICE INVITING TENDER

Sealed rate /percentage rate tenders are hereby by the Executive Engineer Spiti B&R Division HPPWD Kaza on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the below noted work from eligible contractors registered in HPP PWD in appropriate class so as to reach in this office on or before 30.5.2016 upto 3:00 PM and the same shall be opened on the same ay at 3:30 PM in the presence of the Contractors or their authorized representatives who may be present. The tender forms this office against cash payment (non-refundable) on 27.05.2016

The tender shall accompany with earnest money which should be in the shape of NSC/ Time Deposit /saving Bank account in the Post office bank in H.P duly pledged in the favour of undersigned.

Conditional tenders, telegraphic and tender without earnest money will not be entertained The Executive Engineer spiti B& R Division HPPWD. Kaza reserves the right to accept or reject the tenders The tender shall remain valid for 120 days from the day of opening of the tenders.

Sr. No. Name of work	Estimated Cost Rs	Earnest Money	Time
1. M/T of link road Lingti Ramme road km 0/0 to 6/0 (Sh p/l premix carpet surfacing from km 0/0 to 1/250)	918431/-	18370/-	Three Months.

Terms & Conditions:-
1. The contractors /firm shall have Sale Tax Number, Pan Card of the same be attached with the application
2. The intending contractor /firm should have attached copy of registration /Renewal.
3. The intending contractors are request to see the site of the work before submitting the tender.
4. Tender documents shall be issued to those contractors/firm who submitted the certificate from Executive engineer concerned to the effect that he has completed successfully similar nature of works during last three years in respect of tarring work.
5. The Executive Engineer reserve the right to reject /accept any or all the tenders without assessing any reasons.

Adv. No.-0239/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-PROCUREMENT NOTICE
" INVITATION FOR BIDS(IFB) "

Executive Engineer, Dalhousie, Division HP PWD Dalhousie on behalf of Governor of Himachal Pradesh invites the item rate bids in electronic tendering system . for construction of the following works form the eligible and approved contractors registered with HP PWD.

Sr. No. Name of work	Estimated Cost (Rs)	Earnest Money (Rs)	Cost of Tender form (Rs)	Class	Completion Period
1. C/o Shahpur Sihunta road Km 0/0 to 24/0 (SH:Providing Wire Crate protection work with P.C.C. Pusta at km 14/604 to 14/644)	12,26,561/-	24,530/-	500/-	D&C Only	Two Months.

1. Date of release of invitation for Bids through e- procurement **25.04.2016**.
2. **Cost of Bid Form:** As mentioned above (non-refundable) in form of demand draft in favour of executive engineer Dalhousie HP PWD Dalhousie (HP).
3. **Availability of Bids Document and mode of submission:** the bid document is available online and bid should be submitted online on website http:hp-tenders.gov.in bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bid the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA) Aspiring bidders who have not obtained the user ID and Password for participating in e-tendering in HP PWD may obtain the same from the ***Website:http:hptenders.gov.in.*** Digital Signature Certificate is mandatory issued form authorized CAs can use the same in this tender.
4. **Submission of Original Documents:** The original instrument in respect of cost of document and EMD should be submitted to the Tender inviting Authority i.e. Executive Engineer Dalhousie HP PWD Dalhousie by registered post Courier latest (3) working days from the day of technical bid opening.
5. Last Date/Time for receipt of bids through e-tendering date **17.05.2016 upto 11:00AM.** and will be opened on same ay **11:30AM.**
6. The site for the work is available.
7. The Bidder shall submit the Affidavit for not having more than two works in hand at time of opening of Bid.
8. Only online Submission of bids is permitted therefore, bids must be submitted online on website *http:hptenders.gov.in.* The bids shall be opened on **17.05.2016 upto 11.30 AM** in the office of Executive Engineer, Dalhousie, Division HP PWD Dalhousie by the authorized officer. In the interest of of tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bid as specified the bid will be opened on the next working day at the same time and venue.
9. The bid for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than ninety days after the deadline date of bid submission.
10. The tender for above works of the contractor shall be accepted who have their own Hot mix Plant/Mini Mix Hot Plant & Road Roller and ownership Proof thereof shall be uploaded on the website with tender of each work.
11. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-0211/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

नशीले पदार्थों के अन्तर्राज्यीय अवैध व्यापार से सख्ती से निपटना आवश्यक-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि नशीले पदार्थ एक अन्तर्राष्ट्रीय खतरा बन चुके हैं तथा इस समस्या से सख्ती के साथ निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा यदि निकट भविष्य में हम अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय बुराई को समाप्त करने के लिये लोगों की भागीदारी ज़रुरी है।

मुख्यमंत्री कुल्लू में मादक अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान(आईएनएसए) द्वारा 'हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की समस्या, सच्चाई की तलाश एवं समाधान' विषय पर आयोजित नशीले पदार्थों पर नियन्त्रण के लिये राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) द्वारा वित्त पोषित तीन दिवसीय सम्मेलन के शुभारम्भ की अध्यक्षता कर रहे थे।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि नशीली दवाओं का व्यसन एवं दुरुपयोग अनेक परिवारों, समुदायों तथा कानून प्रवर्तन ऐजेन्सियों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के कारण बहुमूल्य मानव जीवन समाप्त हो रहा है और अनेक लोगों के जीवन के उपयोगी वर्ष बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व मादक द्रव्य रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2013 के दौरान एक करोड़ 87 हजार मौतें नशीले पदार्थों से सम्बद्ध थीं और ये आंकड़ें इससे भी कहीं अधिक हो सकते हैं।

मुख्यमंत्रे ने कहा कि एक राष्ट्र होने के नाते हमें सांसारिक वस्तुओं पर अनावश्यक धन को खर्च करने से रोकने की आवश्यकता है तथा अपनी राष्ट्रीय निधि को वैध एवं अवैध नशीले पदार्थों से जानलेवा नुकसान को रोकने तथा इसके बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिये उपयोग में लाना चाहिए।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि अभी तक भारतवर्ष की आबादी एक अरब से अधिक हो चुकी है तथा निरन्तर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश असाधारण रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहां की संस्कृति, सामाजिक मूल्य, जनसंख्या तथा आर्थिकी में तेजी के साथ बदलाव आ रहा है तथा इन सभी दबावों का लोगों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशीली दवाएं एवं मादक द्रव्य विकट समस्याएं हैं जिनसे छोटी आयु के स्कूली बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जब व्यक्ति इन व्यसनों का आदी हो जाता है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति किस आयु अथवा सामाजिक रुतबे का है। उन्होंने कहा कि इन पदार्थों के निरन्तर सेवन के परिणाम सदैव दुःखद होते हैं। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थ हमारी पीढ़ियों को निशाना बना रहे हैं तथा ड्रग माफिया और तस्करों के बीच सम्पर्क पर पैनी नज़र रखते हुए इनसे सख्ती के साथ निपटने की आवश्यकता है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि जहां तक हमारे राज्य एवं पड़ोसी राज्यों का सम्बन्ध है, यहां पिछले कुछ समय से नशीली दवाओं का सेवन एवं इनका व्यापार एक गम्भीर मुद्दा बन चुका है। कानून प्रवर्तन एजेन्सियों को पड़ोसी राज्यों से अंतर्राजीय तस्करी को रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह पाया गया है कि पंजाब सीमा से लगते क्षेत्रों में ड्रग माफिया काफी सक्रिय है और हर हाल में इस पर अंकुश लगाने की ज़रुरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लम्बे अर्से से भांग की खेती एवं उत्पादन की गहरी जड़ें हैं तथा इसका लोगों की आजीविका से सीधा संबंध है और उनकी आय का मुख्य साधन है। उन्होंने कहा कि इसका संबंध हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से भी है। ये क्षेत्र काफी दुर्गम हैं तथा यहां पहुंचने में दिनों लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भांग और अफीम की ही खेती होती है तथा इन क्षेत्रों में यह लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश में इस समस्या से निपटने के लिए लोगों की आर्थिकी के लिए उन्हें केन्द्रीय राशि प्रदान करके नकदी फसलों व फलों के उत्पादन जैसे विकल्प उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि लोग भांग व अफीम की खेती एवं उत्पादन से अर्जित होने वाली आय से अधिक कमा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में भांग एंव अफीम की खेती के लिए कुछ क्षेत्र जाने जाते थे, लेकिन विकल्प के रूप में इन क्षेत्रों में बागवानी विशेषकर सेब इत्यादि नकदी फसलों तथा दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से कृषि व्यवस्था में बदलाव आया है और लोग अब अच्छी कमाई कर रहे हैं।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि नशीले पदार्थों तथा युवाओं में इनकी प्रवृत्ति जैसी समस्याओं का निराकरण करते समय अन्य बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिनमें सिन्थेटिक नशीले पदार्थों का वैध अथवा अवैध तौर पर उत्पादन कर रहे मादक उद्योगों, जो सुव्यवस्थित दिखते हैं तथा इनकी एक सुनियोजित एवं प्रयोजक विपणन व प्रचार रणनीति है। ये उद्योग इन पदार्थों की खपत के पैटर्न पर सतर्कतापूर्वक अनुसंधान करते हैं तथा नई-नई मण्डियां विकसित करके नशीले पदार्थों को अवैध रुप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उच्च तकनीकों को अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी तथा देश को बचाने के लिए इस प्रकार के नेटवर्क से निपटना होगा।

मुख्यमंत्री धर्मशाला में 7 मई को आई.पी.एल. मैच में उपस्थित रहेंगे

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 7 मई, 2016 को धर्मशाला में मुम्बई इण्डियनज़ तथा किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेले जाने वाले इण्डियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के उद्घाटन मैच में उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने दी।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बॉलीवुड सिने स्टार प्रिटी जिंटा ने भी मैच के सम्बन्ध में उनसे बात की है तथा मुख्यमंत्री से मैच में शामिल होने का आग्रह किया है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धर्मशाला में होने वाले सभी क्रिकेट मैचों के लिये पूर्ण सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त, हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी।

शर्मा ने कि उन्होंने मुख्यमंत्री को निजी तौर पर आईपीएल मुकाबलों के बारे में अवगत करवाया है तथा मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में मैच के दौरान उपस्थित रहने पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रकार की खेलों को बढ़ावा देने व सहयोग के लिये प्रयासरत है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इसी दिन नगर निगम धर्मशाला के नव-निर्वाचित सदस्य दाड़ी में प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धर्मशाला में नगर निगम के टाउन हॉल की आधारशिला रखने के उपरांत धर्मशाला में ही हिमुडा के वृत कार्यालय तथा उपमण्डल स्तरीय भू-संरक्षण कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सात अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सीटीओ चौक शिमला से सात अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के लोगों को समर्पित किया। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इन अग्निशमन वाहनों को ऊना, मनाली, नालागढ़, तिलकनगर तथा अग्निशमन पोस्ट बैजनाथ, सरकाघाट, घुमारवीं अग्निशमन केन्द्रों को भेजा गया है। इन वाहनों को मिलाकर विभाग में अग्निशमन वाहनों की कुल संख्या 138 से बढ़कर 145 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार अग्निशमन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के प्रयास कर रही है तथा चरणबद्ध तरीके से अग्निशमन केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

फाश-कम चौकीदार-कम माली के लिये साक्षात्कार 27 अप्रैल को

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय फाश-कम-चौकीदार-कम माली के पदों को किन्नौर, लाहौल-स्पिति, ऊना, कांगड़ा, चम्बा तथा कुल्लू जिलों के उम्मीदवारों के लिये 27 अप्रैल, 2016 से साक्षात्कार निर्धारित किये गए हैं। साक्षात्कार प्रातः 9.30 बजे से हिमाचल प्रदेश सचिवालय (गेट नम्बर 4/स्वागत कक्ष) में लिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र भेजे जा रहे हैं और यदि किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो वह साक्षात्कार से एक दिन पूर्व सम्बन्धित अधिकारी से साक्षात्कार पत्र की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये दूरभाष नम्बर 0177-2880449- 2880584 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

एच.ए.एस. परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं प्रारूप के अन्तिम मसौदे का अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के.एस. तोमर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हिमाचल प्रशासनिक सेवा (एच.ए.एस.) परीक्षा के मुख्य भाग के नए पाठ्यक्रम को आइ.ए.एस. परीक्षा पद्धति के अनुकूल अनुमोदित किया गया। यह पाठ्यक्रम जनवरी 2017 के दौरान आयोजित की जाने वाली एच.ए.एस. परीक्षा से कार्यान्वित होगा। बैठक में आयोग के सदस्य प्रदीप चौहान, आर. एस. नेगी और डा. मान सिंह तथा आयोग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

तोमर ने कहा कि प्रस्तावित सूक्ष्म पाठ्यक्रम को आयोग की वैबसाईट (http://hp.gov.in/hppsc/) पर सभी इच्छुक अभ्यर्थियों एवं आम जनता की जानकारी एवं सुझावों के लिए अपलोड किया गया था। इस नए पाठ्यक्रम के निर्माण का दायित्व आयोग के पूर्व सदस्य प्रो. जे. सी. शर्मा को सौंपा गया था। इस कार्य को अन्तिम रूप देने के लिए बीस से अधिक विभिन्न विशेषज्ञों, विद्वानों एवं आचार्यों का सहयोग लिया गया।

उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम का अन्तिम मसौदा इच्छुक अभ्यर्थियों के प्रयोग के लिए आयोग की वैबसाईट पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। नए प्रारूप में दो वैकल्पिक विषयों के स्थान पर एक ही वैकल्पिक विषय का चयन किया गया है जो अधिकतम 200 अकों का तय हुआ है। इसके दो प्रश्न पत्र प्रत्येक 100 अकों के निर्धारित किए गए हैं। इस व्यवस्था को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के अनुरूप किया गया है।

एच.ए.एस. प्रारम्भिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र प्रत्येक 200 अंक के होंगें जिसमें एक सामान्य अध्ययन एवं दूसरा ऐपटिट्यूड टेस्ट का होगा। इस परीक्षा में सफलता के लिए योग्यता सूची में स्थान निर्धारण के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र में प्राप्त अंक ही मान्य होगें। परन्तु साथ में ऐपटिट्यूड टेस्ट के प्रश्नपत्र में 33 प्रतिशत अकों का अर्जन अनिवार्य शर्त रहेगी।

मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी व हिन्दी विषय प्रत्येक 100 अंकों के होगें जिनमें 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य शर्त होगी। सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र एक, दो व तीन प्रत्येक 200 अंक के होंगे। अंग्रेजी भाषा में निबन्ध 100 अंकों का, वैकल्पिक विषय 200 अंकों तथा साक्षात्कार 150 अंकों का होगा। इस तरह कुल अंक 1050 होंगे।

तोमर ने कहा कि नए प्रारूप को अपनाने से सभी सकायो के विद्यार्थियों को अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार अंक प्राप्त करने का न्यायसंगत अवसर प्रदान किया गया है। कुछ वैकल्पिक विषयों का जो दबदबा अन्तिम योग्यता सूची के लिए मापदण्ड बना रहता था अब उसे तर्कसंगत किया गया है, जिसमें वैकल्पिक विषय में अधिकतम अधिमान 200 अकों का ही होगा। अब वैकल्पिक विषय के अतिरिक्त मुख्य विषयों द्वारा ही अन्तिम योग्यता सूची तय की जाऐगी। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्नपत्रों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूरा कर आयोग की वैबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

मण्डी जिला में सरकार की योजनाओं का सफल कार्यान्वयन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर 15 अक्तूबर, 2015 को आरंभ किए गए 'मण्डी विकास अभियान' के सफल कार्यान्वयन की हि.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष किरण धांटा ने सराहना की है।

उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत जिले में मुख्यतः चार घटकों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया गया है, जिनमें 'मेरी लाडली', आर्थिक सशक्तिकरण, स्वच्छता तथा आपदा प्रबंधन शामिल हैं। राज्य सरकार ने कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए मण्डी जिला के उपायुक्त संदीप कदम को सीविल सेवाएं पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लिंग अनुपात में कमी चिंता का विषय है और 'मेरी लाडली' अभियान से जिले में लिंग अनुपात में आशातीत सुधार हुआ है।

आयोग की सदस्य पूजा शर्मा, कुसुम वर्मा, श्वेता राणा, रोशन शर्मा और राजेंद्र मोहन भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना.....चाणक्य

सम्पादकीय

केजरीवाल बनाम भाजपा-कांग्रेस

आज प्रदेश की राजनीति में केजरीवाल एक ऐसा नाम बन गया है जिसका जिक्र किये बिना कोई भी राजनीतिक चिन्तन/बहस पूरी नहीं हो सकती। ऐसा इसलिये है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में देश की जनता ने भाजपा के पक्ष में एकतरफा फैसला देकर जो संकेत दिया था उसे दिल्ली और बिहार विधान सभा चुनावों में एकदम पलट दिया। दिल्ली में केजरीवाल की आप ने ऐसा राजनितिक इतिहास रचा है शायद उसे ''आप'' भी दूसरी बार न दोहरा सके। बिहार में भी आप ने स्वयं चुनाव न लड़कर नीतिश, लालू और कांग्रेस के गठबंधन को सक्रिय समर्थन देकर अपने को राजनीकि गणना और विश्लेषण में बनाये रखा है। आज ''आप'' पंजाब विधानसभा चुनावों के लिये कांग्रेस तथा अकाली-भाजपा गठबन्धन के विकल्प के रूप में चर्चित होता जा रहा है। पंजाब की अंतिम राजनीतिक तस्वीर क्या उभरती है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन यह तय है कि वहां पर आप को अनदेखा करना संभव नही है। 2014 के लोकसभा चुनावों में आप पहली बार राजनीतिक पटल पर उभरी और आज भाजपा-कांग्रेस के संभावित विकल्प की गणना तक पहुंच चुकी है। यह अपने में एक बड़ी उपलब्धि है । आप को इस मुकाम तक पहुंचाने में केजरीवाल की भूमिका प्रमुख रही है। बल्कि यह कहना ज्यादा संगत होगा कि कांग्रेस के अन्दर जो स्थान नेहरू गांधी परिवार का है आप में वही स्थान केजरीवाल का बनता जा रहा है। केजरीवाल एक तरह से आप का प्लस और माईनस दोनों बन चुका है। ऐसा होने के बहुत सारे कारण है जिन पर चर्चा की जा सकती है। केजरीवाल का बतौर मुख्यमन्त्री अपने पास एक भी विभाग को न रखना। एक ऐसा हथिहार बन गया है जिसके कारण वह निःसंकोच भ्रष्टाचार की हर शिकायत पर कारवाई करने का दम दिखा रहे हैं।

लेकिन आज 'आप' को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने के लिये उन्हें हर राज्य में अपनी टीम का चयन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि वहां भी उन्हे दूसरे केजरीवल ही मिलें। आज केजरीवाल और मोदी की केन्द्र सरकार में हर समय टकराव चल रहा है। केजरीवाल के 67 विधायकों की टीम में बहुत सारे चेहरे ऐसे भी रहे होंगे जिनके बारे में सारी जानकारियां उनके विधायक बनने के बाद मिली हों क्योंकि चुनाव के समय एक लहर थी जिसमें गुण दोष की परख कर पाना संभव नहीं था। लेकिन आज अन्य राज्यों में संगठन खड़ा करते समय गुण दोष को नजर अन्दाज करना हितकर नही रहेगा। केजरीवाल ने जिस तरह से भाजपा के नितिन गडकरी के खिलाफ पूर्ति उद्योग समूह को लेकर हमला बोला था उसके कारण गडकरी को अध्यक्षता का दूसरा कार्यकाल नहीं मिल पाया था। लेकिन गडकरी ने जब अपने उपर लगे आरोपों को लेकर अदालत में मानहानि दायर किया तब केजरीवाल को वह आरोप प्रमाणित करने भारी पड़ गये थे। परन्तु अब जब उसी तर्ज पर केजरीवाल ने क्रिकेट के मुद्दे पर अरूण जेटली को घेरा है तब स्थितियां अलग हैं। क्योंकि आज दिल्ली सरकार की अपनी जांच रिपोर्ट और भाजपा सासंद कीर्ति आजाद के जेटली पर आरोप केजरीवाल के स्टाक में मौजूद हैं।

लेकिन जिस ढंग से केजरीवाल ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को चुनौति दे रखी उसका राजनीतिक बदला लेने के लिये भाजपा राज्यों में अपने लोगों को आप में भेजने की रणनीति बनाकर 'आप' को तोड़ने का प्रयास अवश्य करेगी। क्योंकि भाजपा और 'आप' का सत्ता में आना अन्ना आन्दोलन का ही प्रतिफल है लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि अन्ना का सारा आदोंलन संघ प्रायोजित था और आज उसी आन्दोलन का नाम लेकर भाजपा और उसके समर्थित संगठनों के लोग आप में घुसने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज भाजपा को जो राजनितिक चुनौती आप से है वह कांग्रेस से नहीं है। भले ही कांग्रेस आज भी सबसे बड़ा राजनितिक संगठन है और भाजपा जन समर्थन खोती जा रही है लेकिन कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग चुके हैं उनके साये से वह अभी तक मुक्त नहीं हो पायी है। कांग्रेस ने अपने किसी भी नेता को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हटाया नही बल्कि यदि ध्यान से देखा जाये तो मोदी सरकार ने भी कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर से ध्यान हटाना शुरू कर दिया है। जबकि देश में सत्ता परिवर्तन भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। लेकिन आज भ्रष्टाचार की जगह कुछ दूसरे मुद्दे उछाल दिये गये हैं और भ्रष्टाचार पृष्ठभूमि में चला गया है। केजरीवाल और आप को भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनने के लिये इस स्थिति पर विचार करना होगा।

सरकार बंदरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए कृतसंकल्प

शिमला। प्रदेश सरकार किसानों को बंदर समस्या से निजात दिलाने के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते प्रदेश में किसानों की फसलों को बन्दरों, आवारा पशुओं तथा जंगली जानवरों से बचाने के लिए 25 करोड़ रु की मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना इस वित्त वर्ष से प्रदेश में आरम्भ की गई है, जिसके तहत किसानों को अपने खेतों में बाड़ लगाने के लिए 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

किसानों को बंदरों की समस्या से निजात दिलाने के उपायों के तहत प्रदेश में 8 नसबंदी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें अभी तक एक लाख से अधिक बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए प्रदेश में एक और नया नसबंदी केन्द्र शिमला जिला के तहत कानिया नाला (सैंज) में शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा।

नसबंदी किए गए बंदरों के पुनर्वास के लिए वन वाटिकाएं स्थापित करने की कार्य-योजना तैयार की गई है, जिसके तहत आरम्भ में चिंतपूर्णी व पॉवंटा साहिब में एक-एक वन वाटिका बनाई जाएगी तथा बाद में इन वन वाटिकाओं की सफलता के पश्चात् अन्य उपयुक्त स्थानों पर इस प्रकार की वन वाटिकाएं बनाने पर विचार किया जाएगा।

सरकार के इन्हीं प्रयासों के चलते प्रदेश में गत् दो वर्षों के दौरान लगभग 18,500 बंदरों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। यह खुलासा हाल ही में प्रदेश में बंदरों की संख्या की स्थिति को लेकर मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के वन मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में हैड काऊंट मैथड (Head Count Method) द्वारा की गई बंदरों की गिनती के अनुसार प्रदेश में बन्दरों की संख्या 2,26,086 आंकी गई थी जोकि सरकार के प्रयासों के चलते वर्ष 2015 में घटकर 2,07,614 हो गई है। पिछले एक दशक से प्रदेश में बंदरों की संख्या में कमी दर्ज की गई। वर्ष 2004 के आंकलन के अनुसार प्रदेश में बंदरों की संख्या 3,17,512 थी।

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में घटती बंदरों की संख्या का मुख्य कारण नसबंदी माना गया है, जिसे भविष्य में भी जारी रखने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट के तहत प्रदेश में 27,276 कि.मी. क्षेत्र बदरों के रहने के अनुकूल है। अधिकतर वन मण्डलों में बंदरों की संख्या में कमी आई है, लेकिन नूरपूर, रेणूकाजी, बिलासपुर, रोहड़ू, धर्मशाला, पांगी व डलहौजी वन मण्डलों में वानर संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है।यह मण्डल या तो प्रदेश के उतर-पश्चिम या दक्षीण-पूर्व सीमाओं पर स्थित हैं। रिपोर्ट में वन वृतों व वन मण्डलों की अधिक संख्या वाले बीट के बारे में भी उल्लेख किया गया है। कुल 348 बीटों को हॉटस्पोट बीट के रूप में माना गया है, जोकि 83 वन परिक्षेत्रों में हैं।

रिपोर्ट के तहत वानरों की संख्या का आंकलन पथ सर्वेक्षण प्रणाली (Trail Survey using transact Method) एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographical Information System) के द्वारा किया गया है। सर्वेक्षण कर्मचारियों द्वारा पूरे प्रदेश में जून से जुलाई, 2015 तक 2631 पथों के 12,782 कि.मी. रास्तों पर किया गया है तथा इसमें वातावरण व ऊँचाई आदि के 22 मानकों का अध्ययन भी किया गया है। इन मानकों के आधार पर तथा वैज्ञानिक आंकलन विधि द्वारा वानरों की गणना की गई है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश इस तरह के आंकलन में देश का पहला राज्य बन गया है।

यही नहीं वानरों द्वारा मनुष्यों पर हमलों की घटनाओं में भी कमी आई है। सरकार वानर समस्या के प्रति गम्भीर है तथा प्रभावित व्यक्तियों को क्षति के अनुसार मुआवजा भी दिया जा रहा है तथा वर्तमान सरकार द्वारा इसके तहत मिलने वाले मुआवजे में समुचित बढ़ौतरी की गई है। जंगली जानवरों के कारण मानव मृत्यु पर मुआवजा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपये किया गया है जबकि गम्भीर चोट में यह राशि 33 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार तथा साधारण चोट में 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार की गई है। अब तक सरकार 2200 मामलों में लगभग एक करोड़ रुपये का मुआवजा प्रभावितों को प्रदान कर चुकी है।

कृषि क्षेत्र में हिमाचल को लगातार दूसरा पुरस्कार

शिमला। कृषि क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2015-16 के लिए लगातार दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। हमीरपुर जिला को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। भारत सरकार ने चार योजनाओं क्रमशः स्वच्छ भारत, ग्रामीण स्वच्छ विद्यालय, प्रधानमंत्री जनधन योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड को प्राथमिकता कार्यक्रमों के अंतर्गत चिन्हित किया है।

पर्वतीय तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में हमीरपुर जिला ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कार्यान्वयन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इस योजना में देश के केवल दो जिलों हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा 'सिविल सेवाएं दिवस' के अवसर पर राष्ट्र स्तरीय समारोह में 21 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार हमीरपुर के उपायुक्त और कृषि उपनिदेशक प्राप्त करेंगे। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

हिमाचल को हाल ही में श्रेणी-2 के राज्यों में वर्ष 2014-15 के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए राष्ट्र स्तर पर 'कृषि कर्मण पुरस्कार' प्रदान किया गया था। एक करोड़ रुपये की नकद राशि का यह पुरस्कार प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पूसा में एक राष्ट्र स्तरीय समारोह में 19 मार्च, 2016 को प्रदान किया था। यह पुरस्कार कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया, अतिरिक्त मुख्य सचिव उपमा चौधरी और कृषि निदेशक एस आर कालिया ने प्राप्त किया था।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी, 2015 को देश के सभी किसानों को तीन वर्षों में मिटी के मानकों एवं विश्लेषण के उपरांत जारी करने के उद्देश्य से आरंभ की थी, ताकि उपजाऊ क्षमता में पोषक तत्व की कमी को पूरा किया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य पौधों से पोषक तत्वों के संतुलित एवं समुचित उपयोग के माध्यम से समेकित पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा रसायनिक खादों के उपयोग को कम करना था।

मृदा स्वास्थ्य के महत्व को देखते हुए राज्य कृषि विभाग ने प्रदेश में इस कार्यक्रम का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया। हिमाचल प्रदेश में तीन वर्षो के दौरान 69635 नमूने लेने का लक्ष्य था, जिसे राज्य ने योजना के पहले ही वर्ष में पूरा कर लिया। इन नमूनों का विश्लेषण साथ-साथ किया जा रहा है और प्रदेश में एक लाख 60 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

भारत सरकार ने कार्यक्रम के अंतर्गत बेहतर उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रदेशों एवं जिलों को चयनित करने के लिए व्यापक प्रक्रिया आरंभ की है। राज्य सरकार ने उपलब्धियों के आधार पर हमीरपुर और बिलासपुर जिलों की सिफारिश की थी। भारत सरकार की टीमों के निरंतर दौरों तथा विस्तृत परस्पर संवाद के उपरांत योजना के अंतर्गत हमीरपुर जिले को पहले पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। जिले ने कार्यक्रम के पहले ही वर्ष में 2015-16 के दौरान शत प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर लिया था। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का कार्य 5 दिसम्बर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के उपलक्ष्य में आरंभ किया था। जिले के सभी 76,140 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड 30 जून, 2016 तक वितरित करना प्रस्तावित है।

योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए कृषि विभाग ने किसान शिविरों का आयोजन किया। राज्य में मिटी के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए 11 प्रयोगशालाएं और सात मोबाईल परीक्षण वाहन हैं।

भारत का उद्देश्य रक्षा तकनीकीय संप्रभुता प्राप्त करना है

भारत तीसरी सबसे बढ़ी सशस्त्र सेना है। उसका वार्षिक बजट लगभग 40 बिलियन डॉलर है जिसका पूंजी अधिग्रहण के लिए सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट में बढ़ोत्तरी हो रही है। भारत रक्षा संबंधी सामग्री के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। राष्ट्र इस स्थिति को बदलना चाहता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि रक्षा सेवाओं को हमेशा अच्छी गुणवत्ता के उपकरण मिले। भारत रक्षा उपकरण प्रौद्योगिकी में पर्याप्त आत्म निर्भरता और स्वदेशीकरण प्राप्त करना चाहता है।

रक्षा खरीददारी प्रक्रिया डीपीपी में महत्वपूर्ण सुधार करने की योजना का खुलासा करते हुए रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने डीईएफईएक्सपीओ 2016 के 9वें संस्करण के दौरान नई डीपीपी की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। यह एक्सपो भूमि, नौसेना और आंतरिक गृह भूमि और सुरक्षा प्रणाली प्रदर्शनी पर हर दो साल बाद आयोजित की जाती है। इस बार इसका आयोजन गोवा में किया गया था। इसमें 47 देशों ने भाग लिया जो स्पष्ट रूप से भारत की अंतरराष्ट्रीय रूप से बढ़ती शोहरत और कद का सूचक है। यह आजतक आयोजित सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी। इस साल की प्रदर्शनी में एक हजार से अधिक भारतीय और विदेशी कंपनियों ने भाग लिया। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारतीय डिजाइन विकसित एवं विनिर्मित (आईडीडीएम) श्रेणी को अब सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। नई डीपीपी में सरल प्रक्रिया, समय सीमा में कमी, निर्णय लेने में तेजी और पारदर्शिता को शामिल किया गया है।

अनुसंधान और विकास के महत्व के बारे में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए पर्रिकर ने कहा कि अनुसंधान और विकास मेरे दिल के बहुत नजदीक हैं। एक इंजीनियर होने के नाते मैं यह जानता हूँ कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। प्रौद्योगिकी में हर वर्ष परिवर्तन हो रहा है और भारत एक ऐसा देश है जहां इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की भरमार है जो अनेक रक्षा जरूरतों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के पर्यवेक्षण में हम आईआईटी, आईआईएससी और एनआईटी जैसे अनेक शैक्षिक संस्थानों के साथ कार्य कर रहे हैं जो इस उद्देश्य को नई ऊंचाई ले जा सकते हैं।

रक्षा मंत्रे ने कहा कि यह डीपीपी 'मेक इन इंडिया' एजेंडा को वास्तविक गति प्रदान कर सकती है और यह देश की अपनी जरूरतों के साथ-साथ निर्यात के लिए रक्षा उद्योग नेटवर्क का निर्माण करने में प्रमुख सफलताएं अर्जित करने के भारत के लक्ष्य में भी मददगार होगी। 'मेक इन इंडिया' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुभारंभ की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ राष्ट्रीय कंपनियों को भी भारत में अपने उत्पादनों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन सचिव अशोक गुप्ता ने एक साक्षात्कार में कहा था कि 2014-15

और 2015-16 के दौरान रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 66 पूंजी खरीदारी मामलों को अपनी मंजूरी दी है जिनकी अनुमानित लागत 1.98 लाख करोड़ रूपये है। इनमें से 88 प्रतिशत मामलों को 'बाई इंडियन एंड बाई एंड मेक इंडियन' श्रेणियों में मंजूरी दी गई है जिसका अर्थ है कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध भारतीय खरीदार द्वारा जारी किया जाएगा और वे स्वयं या विदेशी मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के साथ सहयोग करके इन मदों की आपूर्ति करेंगे। इससे भारी घरेलू मांग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पिछले दो वर्षो के दौरान रक्षा निर्माण में निजी क्षेत्र के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी-

1. रक्षा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को संशोधित किया गया है। अब स्वचालित मार्ग के अधीन 49 प्रतिशत तक समग्र विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है और 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की अनुमति से दी जा सकती है। इस प्रक्रिया को को सरल बनाने के लिए नीति में अनेक शर्तो को हटा दिया गया है।

2. प्रविष्टि बाधा को कम करने के लिए, आईडीआर अधिनियम के तहत औद्योगिक लाइसेंसों (आईएल) को जारी करने के उद्देश्य से रक्षा उत्पादों की सूची संशोधित किया गया है और अधिकांश कंपोनेंट, पार्ट्स, उप-प्रणाली का परीक्षण करने वाले उपकरणों, उत्पादन उपकरणों को सूची से हटा दिया गया है।

3. भारतीय निजी क्षेत्र को समान अवसर मुहैया कराया गया है। उत्पाद एवं सीमा शुल्क लेवी के लिहाज से सार्वजनिक क्षेत्र के पास अब कोई विशिष्ट दर्जा नहीं है।

4. भारतीय एवं विदेशी उद्योग के बीच एक समान अवसर सृजित करने के लिए विनिमय दर विचलन (ईआरवी) सुरक्षा की पूंजी अधिग्रहणों के सभी वर्गो में निजी कंपनियों समेत सभी भारतीय कंपनियों को विदेशी विनिमय घटकों पर अनुमति दी गई है।

5. चूंकि घरेलू उद्योग पूरी तरह घरेलू मांग पर ही आश्रित नहीं रह सकता, इसलिए निर्यातों के लिए समस्त प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब निर्यातों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑन लाइन जारी किए जाते हैं।

6. पहली बार एक विशिष्ट रक्षा निर्यात रणनीति का निर्माण किया गया है और इसे सार्वजनिक किया गया है। इस रणनीति में रक्षा वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों को रेखांकित किया गया है।

7. पूंजी अधिग्रहण का 'मेक' प्रावधान मेक इन इंडिया पहल को साकार करने के लिए एक अहम स्तंभ है। ये 'मेक' परियोजनाएं न केवल वेंडर विकास के लिहाज से पारिस्थितिकी प्रणाली के सृजन में सहायक होंगी, बल्कि उद्योग द्वारा विकास और/ प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए होड़ की शुरूआत भी करेंगी। स्वदेशी तरीके से विकसित ऐसी प्रणालियां रक्षा बाजार में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उपलब्ध होंगी।

8. ऑफसेट्स घरेलू उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक हिस्सा बनने में सहायक होते हैं। जहां तक भारत में व्यवसाय करने का सवाल है, अफसेट क्रियान्वयन विदेशी ओईएम के साथ एक बड़ा मुद्दा रहा है। हम लोगों ने दिशा निर्देशों में उल्लेखनीय रूप से संशोधन करने का कार्य शुरू किया है।

9. सचिव (रक्षा उत्पादन) अशोक गुप्ता ने कहा कि किफायती मानव संसाधन की एक बड़ी संख्या के साथ-साथ इन कदमों को लागू किए जाने के साथ भारत में अभी निवेश किए जाने का सर्वश्रेष्ठ समय है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार उद्योग के लिए नीति, प्रक्रियाओं एवं प्रवर्तक कदमों में बदलाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए अब यह उद्योग पर निर्भर करता है कि वह रक्षा क्षेत्र में निवेश करने के द्वारा इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ उपयोग करे।

पसूका

उत्तर भारत के यात्रियों को मिली भारी राहत

शिमला। उत्तरभारत की ओर जानेवाली ट्रेनों के यात्रियों की तकलीफों को दूर करने के लिए मुम्बई के बीजेपी नेताओं की सक्रियता और केंद्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु द्वारा रेल अधिकारीयों को यात्रियों की परेशानी तत्काल दूर करने के दिए गए कडे निर्देश ने रंग दिखाया और बनारस, गोरखपुर और पटना के लिए नई ट्रेन चलाने की घोषणा हो गयी। केंद्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु को मुम्बई बीजेपी के महामन्त्री अमरजीत मिश्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मिलकर उत्तरभारत की ओर जानेवाले यात्रियों की तकलीफों की जानकारी दी। प्रभु ने पहले मध्यरेल के महाप्रबन्धक सुनीलकुमार सूद, पश्चिम रेल के महाप्रबन्धक अग्रवाल और रेल बोर्ड के अधिकारियों से बात की और मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्हें तुरंत एक्स्ट्रा कोच उपलब्ध करा के नई ट्रेन शुरू करने का निर्देश दिया। प्रभु के आदेश के बाद बीजेपी के प्रतिनिधिमण्डल ने सूद और अग्रवाल से अलग अलग मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल के प्रमुख अमरजीत मिश्र इस बात के लिए अड गए कि आज से ही ट्रेन शुरू की जाये। सूद और रेल बोर्ड के अधिकारियों की काफी जद्दोजहद के बाद 17 डिब्बों की एक नई ट्रेन शुरू करने की घोषणा हुयी। इस बीच मुंबई बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल रेलमंत्री सुरेश प्रभु से सतत संपर्क बनाये हुए था।

रेल महाप्रबन्धक से बात करने के दौरान मुम्बई लोकल ट्रेनों और स्टेशनों का दौरा करने आई रेलमंत्रालय की पैसेंजर एमेनिटीज कमिटी के सदस्य मोहम्मद इरफान अहमद, डा. अशोक त्रिपाठी और नागेश नामजोशी भी मौजूद रहे और वे उत्तरभारत के यात्रियों की तकलीफों को दूर करने की वकालत भी करते रहे।अमरजीत मिश्र ने सूद को बताया कि वर्षो से तकलीफ सहने वाले लम्बी दुरी के यात्रियों के प्रति रेल अधिकारी आखिर कब सहानुभूति

बरतेंगे। उन्होंने प्रीमियम ट्रेन जैसी सुविधा खत्म कर सामान्य यात्रियों के दर्द की ओर ध्यान देने का निवेदन किया। उन्होंने सुझाया कि इलाहाबाद बनारस दरभंगा पटना लखनऊ के लिए कुछ ट्रेन तत्काल शुरू की जाये ताकि आसपास के लोग वहां उतरकर अपने गांव जा सकें। सूद ने इलाहाबाद के रूट पर भारी बोझ होने की बात बताई। इसके बाद गोरखपुर के लिए अनारक्षित डिब्बों की ट्रेन शुरू करने की घोषणा हुई, साथ ही बनारस के लिए आरक्षित और पटना के लिए अनारक्षित ट्रेन चलाने की भी घोषणा हुई।यह गाडियां नियमित रूप से अल्टरनेट डेज चलाई जाएँगी। भाजपा नेता मिश्र ने यह भी मांग की कि अनारक्षित डिब्बों के यात्रियों को ट्रेन में चढाने के लिए किसी भी तरह का बल प्रयोग न किया जाये और पूरे पूरे दिन यात्रियों को लाईन में खडे रखने के बजाय चन्द घण्टे पहले ही कतार लगवायी जाये।

रेलमंत्री सुरेश प्रभु की सक्रियता और तत्काल निर्णय लेने के आदेश के बाद उत्तरभारत के यात्रियों को भारी राहत मिलेगी। मुम्बई बीजेपी के महामंत्री अमरजीत मिश्र ने प्रभु और सुनीलकुमार सूद के प्रति आभार भी माना है। प्रतिनिधिमण्डल में मिश्र के अलावा ईशान्य मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष एडवोकेट दीपनारायण मिश्र, प्रदेश बीजेपी मिडिया सेल के सह संयोजक ओमप्रकाश चौहान, रेल जेड आर यू सी सी मेंबर कैलाश वर्मा, राकेश सिंह, वसीम खान, राज यादव, सप्रे व धरम शर्मा शामिल थे।

केंद्रीय कोश का सही उपयोग करने में नाकाम वीरभद्र सरकार:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। राज्यों के विकास तथा देशवासियों के जीवन स्तर में मजबूती लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाऐं निर्मित की गई है, जिनके तहत राज्य सरकारों को आर्थिक व वाणिज्यिक सहायता प्रदान की जाती है। परन्तु हिमाचल सरकार केंद्रीय फंड का सही उपभोग करने में नाकाम साबित हुई है तथा केंद्र की ओर से दी जानी वाली सहायता राज्य पर काबिज़ कांग्रेस सरकार के कुशासन की वजह से जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है, यह शब्द कहते हुए हमीरपुर सांसद तथा भाजयुमो अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर राज्य सरकार पर जमकर बरसे।

सूबे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर असंतोश जाहिर करते हुए कहा की, आम जनता को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्यों वीरभद्र सरकार केंद्रीय कोश का उपयोग करने में विफल रही है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की चिरकालिक कमी होने के बावजूद हिमाचल राज्य शिक्षा विभाग 130 करोड़ रुपयों का उपयोग करने में नाकामयाब रहा है, जोकि वर्ष 2014-15 के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बजट का 37 प्रतिशत था। वीरभद्र सरकार को अपनी जवाबदेही समझनी होगी तथा इसके कारणों को बताना पड़ेगा।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 'न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि मुख्यमंत्री को राज्य के प्रत्येक विभाग को मिले सरकारी फंड के मूल्य तथा उसके हुए उपयोग का विस्तृत विवरण आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।' एक ओर जहां राज्य सरकार बाजार से 38,000 करोड़ का ऋण ब्याज सहित ले रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा, सड़क व अस्पतालों के नाम पर दिये गए फंड के पैसे का सही उपयोग करने में असक्षम प्रतीत हो रही है।

राज्य सरकार के कार्यो तथा नीतियों पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र जी को जवाब देना होगा कि क्यों राज्य के विद्यालय, अस्पताल व सड़को की हालत जर्जर होती जा रही है? आखिर किन कारणों के चलते सरकारी कार्यालय मानव संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं? और पिछले 30 माह के समय में राज्य के विकास की राह में कांग्रेस सरकार ने वीरभद्र जी की अगुवाई में अब तक क्या कदम उठाऐ है ?

मेरे अनुसार तो राज्य सरकार हिमाचल के लोगों को गहरे कूप की ओर ही ले रही है।

CII ने वीरभद्र सरकार को सराहा

शिमला/शैल। हिमाचल में लगे उद्योगों के उद्योगपतियों की सरकार के समक्ष पैरवी करने वाली संस्था सीआईआई की हिमाचल परिषद ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए देश व बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इवेंट मीट कन्क्लेव हिमाचल में योजना चलाने का एलान किया है। इसे तीन सालों में सभी जिलों में शुरू कर दिया जाएगा। खुराना ने कहा कि इस सिलसिले में ई लर्निंग नामक एनजीओ को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है। खुराना व सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र

आयोजित कराने का एलान किया है। सीआईआई की हिमाचल इकाई के अध्यक्ष संजय खुराना ने कहा कि उन उद्योगपतियों को इससे हिमाचल को समझने में मदद मिलेगी।

उन्होंने विपक्षी पार्टी भाजपा के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि हिमाचल में पिछले तीन सालों में निवेश नहीं हुआ है। खुराना ने दलील दी कि मौजूदा उद्योग अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए 15 सौ करोड़ का निवेश कर रहे है। खुराना ने कहा कि बाहर से निवेशक एक दम नहीं आता। कंन्क्लेव के रिजल्ट दो तीन साल बाद सामने आएंगे। औद्योगिक पैकेज की गैरमौजूदगी में सीआईआई ने हिमाचल सरकार से मौजूदा उद्योगों के लिए रिटेंशन पॉलिसी के तहत इंसेटिंव देने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि बजट में इस तरह की घोषणाएं हुई भी है जिसकी वो सराहना करते है।

इसके अलावा सीआईआई ने जिला सोलन या सिरमौर में से किसी एक जिला में युवतियों को कैरियर बनाने में मदद करने के लिए पायलट स्तर पर गुलेरया ने उस दावे को नकार दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि हिमाचल से उद्योगों का पलायन हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमेशा ही जाते हैं या उनमें से कुछ असफल हो जाते है। ये बड़ा मसला नहीं है।

हिमाचल में निवेश में सबसे बड़ी बाधा को क्नैक्टिविटी है। बद्दी बरोटी वाला को रेलवे से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा चंडीगढ़ में मैट्रो की बात हो रही है। इसे मूल्लापुर से होकर बीबीएन तक बढ़ा दिया जाए तो मदद मिलेगी। इसके अलावा यहां पर फोरलेन का काम जल्द होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल के पंडोगा व दभेटा में दो नए औद्योगिक क्षेत्र उभर रहे है जो सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को उद्योग लगाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए ताकि वो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें।

उन्होंने माना कि कई उद्योगों में हिमाचलियों की तादाद 70 फीसदी से कम है व इसके अलग-अलग कारण है। जबकि कई उद्योगों में 80 से 90 प्रतिशत हिमाचली है।

सिरमौर से किसी भी परिवार ने पानी की समस्या से पलायन नहीं किया-विनय

शिमला/शैल। मुख्य संसदीय सचिव लोक निर्माण, विनय कुमार ने कहा है कि सिरमौर जिला में वर्तमान में पेयजल की इतनी गम्भीर समस्या नहीं है, और न ही जिला से किसी भी परिवार द्वारा पेयजल समस्या के कारण पलायन किया गया है।

मुख्य संसदीय सचिव उपायुक्त कार्यालय में सिरमौर जिला में पेयजल समस्या को लेकर अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने कहा कि सर्दी के मौसम में बहुत कम वर्षा होने के कारण जिला में जलस्तर में कमी आनी शुरू हो गई है, परन्तु जिला में पानी को लेकर पलायन करने जैसी स्थिति नहीं है । उन्होने कहा कि जिला की पंचायत पालियों के गांव गुमटी, क्यारी इत्यादि में कुछ गुज्जर परिवार रहते है जोकि हर वर्ष अपने मवेशियों को लेकर रोपड इत्यादि क्षेत्र की ओर चले जाते है।

उन्होने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जो हैंडपंप सूख गए हैं उन्हें पुनः चालू करने के लिए प्रभावी कदम तुरन्त उठाए जाऐं और जिन क्षेत्रों मे पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है ऐसे क्षेत्रो में नए हैंड पंप स्थापित करने के अतिरिक्त टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

सिरमौर जिला में पेयजल और सिंचाई योजनाओं बारे जानकारी देते हुए सीपीएस ने बताया कि जिला में 854 पेयजल योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसमें 603 ग्रेवीटी, 228 उठाऊ और 23 नलकूप शामिल है । इसके अतिरिक्त जिला में सिंचाई की 191 योजनाएं कार्यरत हैं जिसमें 60 उठाऊ सिंचाई योजनाएं, 111 ग्रेवीटी व 20 नलकूप के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

उपायुक्त सिरमौर बीसी बडालिया ने बताया कि जिला में पेयजल समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए आईपीएच तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से सर्वेक्षण करवाया जा रहा है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंनें कहा कि जिला से किसी भी परिवार ने पीने का पानी न होने के कारण कोई पलायन नहीं किया है। उन्होने कहा कि गर्मी बडने के कारण जल स्त्रोत अवश्य सूखने लगे है, परन्तु सूखे से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक प्रबन्ध किए गए है। उन्होने विभाग को टैंकर लगाने के लिए शीघ्र टैंडर करने के निर्देश दिए।

उन्होने कहा कि नाहन शहर में उपलब्ध पेयजल के समान मात्रा में आबटन के लिए आईपीएच विभाग को निर्देश दिए गए है। उन्होने जानकारी दी कि नाहन शहर के लिए आपूर्ति करने वाली उठाऊ खैरी-बोगरिया घाट योजना की आवश्यक मुरम्मत और पाईप बदलने के लिए सवा चार करोड की राशि स्वीकृत करके टैंडर भी करवा दिए गए है तथा इस योजना की मुरम्मत का कार्य भी शीघ्र आरंभ होने जा रहा है।

इसके अतिरिक्त नाहन शहर के लिए दूसरी जलापूर्ति योजना नेहरस्वार की आवश्यक मुरम्मत के लिए साडे आठ करोड की राशि स्वीकृत करके टैंडर भी करवा दिए गए है।

उपायुक्त ने जिला और विशेषकर नाहन शहर के लोगो से अपील की है कि पानी का उचित मात्रा में सदुपयोग करें और पीने के पानी से किचन गार्डनिंग न करें । उन्होने आईपीएच विभाग को निर्देश दिए शहर में ओवर फ्लो होने वाली टंकियों में वॉल लगाने के लिए लोगों को जागरूक करें और टूल्लू पंप लगाने वालों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होने विभाग को निर्देश दिए कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल के महत्व बारे जागरूक करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करे और लोगों से आग्रह किया जाए कि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाए ।

उपायुक्त ने जानकारी दी कि पशुपालन विभाग को चारा इत्यादि के प्रबन्धन हेतू आवश्यक निर्देश दिए गए है और यह मामला सरकार से ध्यान में भी लाया जा चुका है ।

अधीक्षण अभियंता आईपीएच, बीएस भाटिया ने जानकारी दी कि जिला में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए विभाग द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे है, और लोगों को पानी के महत्व बारे जागरूक किया जा रहा है।

इस अवसर पर उपायुक्त द्वारा पॉलियों पंचायत की प्रधान शकुंतला देवी और उप प्रधान भूषण लाल तथा कौलावाला भूड की प्रधान से दूरभाष पर पेयजल समस्या बारे जानकारी हासिल की और पॉलियों पंचायत की प्रधान ने बताया कि इस पंचायत से हर वर्ष कुछ गुज्जर परिवार अपने मवेशियों को लेकर हरियाणा अथवा रोपड इत्यादि क्षेत्र में अकसर जाते है इसके अलावा किसी भी स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या के कारण पलायन नहीं किया है। पंचायत प्रधानों ने बताया कि उनकी पंचायतों में पेयजल की ऐसी गंभीर समस्या नहीं है ।

सोलन बनेगा तीसरा नगर निगम मुख्यमंत्री ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन शहर को नगर निगम का दर्जा प्रदान करने की सैद्धांतिक मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सोलन शहर का और अधिक एवं योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही इस शहर को प्रदेश का तीसरा नगर निगम बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा।

डॉ. शांडिल ने कहा कि सोलन प्रदेश का प्रवेश द्वार है, और इस शहर का पिछले कुछ वर्षो के दौरान काफी विस्तार हुआ है। शहर की जनसंख्या में भी 10 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज की गई है जो एशिया में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि शहर के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए उन्होंने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में इस शहर को नगर निगम का दर्जा दिलाने का वायदा किया था, जिसके लिए वह पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सोलन जिला तथा शहर के लोगों का भी सोलन के विकास एवं इसे नगर निगम का दर्जा दिलवाने के लिये आभार प्रकट किया है।

उन्होंने कहा कि सोलन शहर को नगर निगम का दर्जा मिलने से यहां विकास में तेजी आएगी तथा शहर में अधोसंरचना के विस्तार से और अधिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त शहर वासियों को पार्क, खेल मैदान, बेहतर स्ट्रीट लाईटें व अच्छी सड़क सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

डा. शांडिल ने कहा कि शीघ्र ही जिला प्रशासन प्रदेश सरकार को नगर निगम संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोलन शहर के बहुआयामी विकास के प्रयास जारी हैं। शामती बाईपास का कार्य आरंभ कर दिया गया है, जिसके हाल ही में नाबार्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस बाईपास के बनने से सोलन शहर में यातायात का दबाव कम होगा और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

एचपीसीए लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई संस्था होनी चाहिए:वीरभद्र सिंह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टाण्डा में सराय भवन की आधारशिला रखने के उपरान्त एच. पी.सी.ए. को लेकर कहा कि वह क्रिकेट के विरूद्ध नहीं हैं, लेकिन एचपीसीए लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई संस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई आपति नहीं है यदि एचपीसीए अपने आप को सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करवाती है और इस बारे पहले भी कहा गया है, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों के मित्र व रिश्तेदार ही एचपीसीए के सदस्य हैं।

उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के सचिवअनुराग ठाकुर, जो एचपीसीए के अध्यक्ष भी है, बिना तथ्य जाने सरकार की आलोचना में लगे रहते हैं। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी लोढ़ा समिति की रिपोर्ट में पाया है कि जो क्रिकेट संगठन मानदण्डों के अनुसार पंजीकृत नहीं है, वे इस प्रकार छल से संस्था को नहीं हथिया सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी हिदायत दी है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड तथा अपंजीकृत खेल निकायों को पैसा कमाने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पुनर्गठन तथा इसे और पारदर्शी निकाय बनाने के सम्बन्ध में जस्टिस लोढा रिपोर्ट की संस्तुतियों से अनुराग ठाकुर को भी इस बारे स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोढा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसी भी राजनेता का लड़का अथवा लड़की खेल निकाय का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा खेल संघों की संस्था के चुनाव पारदर्शी एवं लोकतान्त्रिक तरीके से होने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी खेल संगठनों में पारदर्शिता होनी चाहिए और यह कहना कि वीरभद्र सिंह क्रिकेट के विरोधी है, अनुराग ठाकुर की केवल धारणा मात्र है। सरकार ने कभी भी टी-20 मैच के लिये इन्कार नहीं किया क्योंकि इस विश्व कप के कुछ मैच धर्मशाला में खेले गए तथा अब आई.पी.एल. के मैच मई माह में खेले जाने हैं।

यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गान्धी के हिमाचल प्रदेश के प्रवास के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक उनके कार्यालय में इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, उन्होंने स्वयं सोनिया गांधी को हिमाचल प्रदेश आने तथा किन्नौर में एक बड़ी जल विद्युत परियोजना के लोकार्पण के लिये आग्रह किया है, लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है।

परिसम्पत्तियों की जांच के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया में वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह सब कुछ राजनीति से प्रेरित है तथा विपक्ष उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयकर से सम्बन्धित मामले विभिन्न स्तर पर न्यायालयों में विचाराधीन हैं और इसके बावजूद प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा आयकर विभाग सभी इस मामले की जांच में लगे हैं और यह सब कुछ राजनैतिक प्रतिशोध के कारण किया जा रहा है।

हिमाचल ट्रेवल मार्ट में 11 देशों की मीडिया हस्तियों की रही शिरकत

शिमला/शैल। दुनिया के सैलानियों को हिमाचल की वादियों से रूबरू कराने की मुहिम के चलते हिमाचल टूरिज्म विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे हिमाचल ट्रेवल मार्ट में देश विदेश के ट्रेवल एजेंटों और मीडिया जगत ही हस्तियों की सैर कराएगी। इस मार्ट में जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बुल्गेरिया, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, आस्ट्रेलिया और रशिया से डेलिगेट आ रहे है।

22 तारीख से शुरू हो रहे इस ट्रेवल मार्ट में 10 देशों के पर्यटन से जुड़े प्रतिनिधि, 11देशों की मीडिया हस्तियां शिरक्त कर हिमाचल के पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विरोधी मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि इस मार्ट में यूके, जर्मनी, यूएई, श्रीलंका नेपाल आदि कई देश से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत की हस्तियां शिरक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सैलानियों को इस मार्ट में हिमालय के टूरिस्ट स्थलों से रूबरू कराया जाएगा।

मार्ट में देश के 500 के करीब ट्रेवल एजेंट और हिमाचल के 50 ट्रेवल एजेंट एक दूसरे से बिजनेस टू बिजनेस को लेकर विचार विमर्श करेंगे। करीब 2000 के करीब अप्वाइटमेंटस निर्धारित की गई है।

इसके अलावा बिहार, गोवा, महाराष्ट्र,झारखंड, आंध्रप्रदेश, तेलांगना, गुजरात और छतीसगढ़ जैसे आठ राज्य अपने-अपने राज्यों के टूरिजम को यहां आने वाले डेलिगेट्स व सैलानियों के समक्ष मार्किट करेंगे।

पहले की तरह इस बार भी मेजर मनकोटिया ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को पर्यटन के विस्तार में बड़ी बाधा करार देते हुए जहां अपने ही सरकार पर हमला बोला वहीं पर केंद्र की मोदी सरकार पर भी धावा बोला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बीते दिनों शिमला के लिए उड़ाने भरने के मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल से सौतेला व्यवहार करती रही है। उन्होंने कहा कि बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कहीं मोदी सरकार गैर एनडीए शसित राज्यों से भेदभाव तो नहीं कर रही है।

मनकोटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब शिमला के लिए जल्द ही उड़ाने शुरू होने की उम्मीद है। टेंपल टूरिज्म से लेकर बुद्धिस्ट व ट्राइबल टूरिज्म के क्षेत्र में सैलानियों की आमद की क्षमता को लेकर उन्होंने कहा इस बावत जम्मू कश्मीर व उतराखंड सरकार के साथ साझे पैकेज को लेकर वो बातचीत शुरू की थी लेकिन दोनों राज्यों में सरकारों के अस्थिर होने से ये सिरे नहीं चढ़ पाई। मनकोटिया ने कहा कि किन्नौर, लाहुल-स्पिति से लेकर लेह-लद्दाख तक पैकेज तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। इसे केंद्र सरकार को भी भेजा गया है ताकि तीनों राज्यों का एकीकृत प्लान बने।

उन्होंने कहा कि यहां आने वाली हस्तियों से प्रदेश की झीलों में शिकारा व हाउस बोट जैसे सुविधाएं विकसित करने को लेकर बातचीत की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कालका-शिमला रोड फोरलेन बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है जबकि पठानकोट मंडी रोड भी फोरलेन बनने जा रहा है। जबकि रेलवे में पठानकोट, जोगेंद्र नगर लाइन को ब्रॉडगेज बनाने की मंजूरी मिल गई है।

त्रिपुरा विधान सभा उपाध्यक्ष ई-विधान जानने हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय पहुंचे

शिमला/शैल। देश की सर्वप्रथम ई-विधान प्रणाली जानने हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर पहुंचे

त्रिपुरा विधान सभा के उपाध्यक्ष पवित्र कार ने त्रिपुरा विधान सभा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष बृज विहारी लाल बुटेल से मुलाकात की। इस अवसर पर विधान सभा सचिव सुन्दर सिंह वर्मा तथा निदेशक सूचना प्रोद्यौगिकी हिमाचल प्रदेश विधान सभा धर्मेश कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। त्रिपुरा विधान सभा के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ सदन को देखा तथा ई-विधान प्रणाली की विस्तृत जानकारी हासिल की। बृज बिहारी लाल बुटेल ने त्रिपुरा से आए विधान सभा के उपाध्यक्ष व अन्य अधिकारियों को ई-विधान से होने वाले फायदों के बारे भरपूर जानकारी दी।

बुटेल ने कहा कि ई-विधान एक पर्यावरण मित्र प्रणाली है इससे जहां पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा वहीं हजारों वृक्ष कटने से बचेगें। उन्होंने कहा कि इससे Paper&less काम होगा तथा विकास में गति आएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने से जहां समय की बचत होगी वहीं कार्य में तीव्रता तथा पारदर्शिता आएगी।

इस अवसर पर त्रिपुरा विधान सभा उपाध्यक्ष पवित्र कार ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य हैं जो देश में सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सम्पन्न हुआ है। उन्होंने इसके लिए विधान सभा अध्यक्ष बृज विहारी लाल बुटेल को बधाई दी तथा उन्होंने सदन के रख-रखाव की भी भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने बुटेल से इसे त्रिपुरा विधान सभा में स्थापित करने बारे सहयोग भी मांगा। विधान सभा सचिव सुन्दर सिंह वर्मा तथा तथा निदेशक सूचना प्रोद्यौगिकी हिमाचल प्रदेश विधान सभा धर्मेश कुमार शर्मा ने उन्हें सदन में स्थापित ई-विधान प्रणाली के बारे मे विस्तृत जानकारी दी तथा ई-प्रशिक्षण केन्द्र से भी अवगत करवाया।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अखिल भारतीय चयन रैली 23 मई से

शिमला/शैल। तामिलनाडू वेलिंगटन (नीलगिरी) स्थित मद्रास रेजिमेंटल सेंटर की ब्वायज़ स्पोर्टस कंपनी के लिए एथेलेटिक, बॉक्सिंग तथा वॉलीबाल टीमों में उत्कृष्ट युवा लड़कों के प्रवेश के लिए अखिल भारतीय खुली चयन रैली 23 मई से 28 मई, 2016 को आयोजित की जाएगी। रैली के आयोजन का उद्देश्य चुनिंदा खेलों के लिए प्रतिभाओं का चयन एवं निखार करना है ताकि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिर्स्धाओं में बेहतर प्रदर्शन एवं मैडल हासिल किए जाए सकें।

खेल स्पर्धाओं के लिए शारीरिक और तकनीकी दक्षता की चयन प्रक्रिया भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचों तथा बोर्ड ऑफ आफिसर के अन्तर्गत की जाएगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय के आई.एच.क्यू. तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होने तक यह चयन अस्थायी रहेगा। चयनित खिलाड़ी अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत बुलाए जाएंगे।

पहली अप्रैल, 2014 को 11 से 15 वर्ष की आयु के उम्मीदवार तथा 16 वर्ष आयु के ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर मैडल हासिल किए हैं, चयन के लिए पात्र होंगे। शैक्षणिक योग्यता अंग्रजी और हिंदी में दक्षता सहित कम से कम पांचवी पास निर्धारित की गई है। 12 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 153 से.मी. तथा बजन 35 किलोग्राम, 13 वर्ष के लिए क्रमश: 155 से.मी. व 42 किलोग्राम तथा 14 वर्ष के लिए 160 से.मी. व 47 किलोग्राम निश्चित किया गया है।

इच्छुक उम्मीदवार मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, वेलिंगटन, स्थित ब्वायज स्पोर्टस कंपनी के पीठासीन अधिकारी (चयन) को 23 मई से 28 मई, 2016 के बीच प्रात: 7.00 बजे रिपोर्ट कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष न. 0423-2239059 अथवा मोबाई न. 88607-58811 पर स्पोर्टस कंपनी के आफिसर कमांडिंग से संपर्क कर सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

'अरूण धूमल' कौन है–बहुत कमजोर है वीरभद्र की यह प्रतिक्रिया

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अरूण धूमल की मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के खिलाफ आक्रामकता अब फिर से बढ़ने लगी है। शिमला में वीरभद्र सिंह द्वारा 1974 में हॉलीलाज में पांच हजार में बेचे प्लाट को 2007 में हिमाचल सरकार द्वारा 25 लाख में अधिग्रहण कर लिए जाने

का मुद्दा उछालने के बाद ऊना में पत्रकार वार्ता में ई.डी. द्वारा दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में अटैच की गई अचल सम्पति का मुद्दा उछालकर वीरभद्र को प्रतिक्रिया देने पर विवश कर देना राजनीतिक सन्दर्भों में अरूण धूमल की एक बड़ी सफलता है। अरूण धूमल के आरोपों का यह जवाब देना की अरूण धूमल कौन है वीरभद्र के स्तर के मुताबिक एक बहुत ही कमजोर प्रतिक्रिया है। बल्कि इससे अपरोक्ष में यह प्रमाणित हो जाता है कि इन आरोपों का कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि छोटे धूमल ने हर आरोपों के दस्तावेजी प्रमाण मीडिया के साथ जारी किए हैं। अरूण धूमल के आरोपों पर मोहर लगााते हुए भाजपा विधायकों ने भी वीरभद्र सिंह को चुनौति दी है कि वह इन आरोपों पर मानहानि का मामला दायर करने का साहस दिखाएं। अरूण धूमल और भाजपा के साथ ही एच पी सी ए ने भी वीरभद्र और उनके बेटे विक्रमादित्य के खिलाफ जोरदार हमला किया है बल्कि पहली बार एच पी सी ए ने बिना नाम लिए शान्ता कुमार के खिलाफ भी निशाना साधा है। वीरभद्र पर हो रहे इन हमलों में कांग्रेस संगठन की ओर से कोई भी उनके बचाव में नहीं आया है।

वीरभद्र की ओर से आयी कमजोर प्रतिक्रिया पर यह सवाल उठता है कि क्या वीरभद्र और उनकी सरकार के पास धूमल परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं है? जबकि वीरभद्र बार बार धूमल सम्पतियों की जांच को लेकर बड़े-बड़े ब्यान दागते रहे हैं। विजिलैन्स ने भी धूमल सम्पतियों की जांच को लेकर छपे समाचारों का कभी प्रतिवाद नहीं किया है। राजनीति का यह स्वभाविक नियम है कि अपने विरोधी के आरोप को सीधे नकारने के साथ ही उसके खिलाफ इतना बड़ा और जोरदार आरोप लगा दो कि उसके आगे आपका आरोप स्वत: ही छोटा पड़ जाए। वीरभद्र और उनकी पूरी टीम इस मोर्चे पर बुरी तरह असफल सिद्ध हो रही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि या तो यह टीम पूरी तरह खाली है या फिर वीरभद्र के प्रति उनकी निष्ठाएं बदल चुकी हैं। इसमें चाहे जो भी स्थिति हो यह अन्तत: वीरभद्र के लिए घातक सिद्ध होगी।

इस समय वीरभद्र और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी में दर्ज मामलों की जांच चल रही है। कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाकर इस मामले को यहां तक खींचने में भले ही सफल हो गये हों पर इस मामले को खत्म नहीं करवा पाए हैं। आज जो बड़े बाबू वीरभद्र के चारों ओर घेरा डालकर बैठे हैं उनका अपना स्वार्थ इतना भर ही है कि किसी तरह मुख्यमन्त्री अपना यह कार्यकाल पूरा कर लें। इस कार्यकाल के बाद इन मामलों में उनके परिवार का क्या होता है इससे इस टीम का कोई लेना देना नहीं है। संगठन के तौर पर भी वीरभद्र के गिर्द पुराने हारे हुए नेताओं की एक ऐसी टीम संयोगवश खड़ी हो चुकी है जिसने आगे चुनाव लड़ना ही नहीं है। इस टीम का स्वार्थ भी इतना मात्र ही है कि जब तक वीरभद्र सत्ता में बने रहेंगे तब तक ही उन्हें लाभ मिलता रहेगा। लेकिन जैसे-जैसे धूमल/भाजपा का अटैक वीरभद्र के खिलाफ बढ़ता जाएगा उसी अनुपात में अदालत और जांच एजेन्सीयों पर भी उसका असर पड़ता जाएगा। क्योंकि जब कोई दस्तावेजी प्रमाण मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक होते जाते हैं तब उन्हे नजर अन्दाज कर पाना संभव नहीं रह जाता है। आज वीरभद्र हर रोज इस तरह की स्थिति में घिरते जा रहे हैं और बहुत सम्भव है कि निकट भविष्य में उनके कुछ विश्वस्तों के खिलाफ भी ऐसे ही हालात देखने को मिलें। क्योंकि सूत्रों की माने तो कई पुराने मामलों को ताजा करने की रणनीति पर काम चल रहा है जिसके परिणाम और भी घातक होंगे। माना जा रहा है कि पिछले दिनों एक पत्रकार के माध्यम से वीरभद्र, धूमल और विक्रमादित्य के बीच में हुई बैठक में जो कुछ भी तय हुआ था उसका तत्कालिन लाभ तो कुछ को मिल गया था लेकिन

अब उस बैठक से वीरभद्र के अतिरिक्त अन्य सभी पल्ला झाड़ रहे हैं क्योंकि इस बैठक के बाद बड़ी विजयी मुद्रा में उस पत्रकार को कहा था कि अब भविष्य में अरूण धूमल की जुबान बन्द रहनी चाहिए। लेकिन अरूण धूमल की पत्रकार वार्ताओं से स्पष्ट हो गया है कि यह सब बीते कल की बात हो गई है। राजनीति में इसके कई अर्थ निकलते हैं।

रिज स्थित चर्च की

17.50 करोड़ में होगी रिपेयर या...?

शिमला/शैल। शिमला के रिज स्थित चर्च की 17.50 करोड रूपये में रिपेयर किये जाने का अनुबन्ध 10 सितम्बर 2014 को हस्ताक्षरित हुआ है। आर टी आई के माध्यम से 27-2-16 को बाहर आये इस अनुबन्ध की शर्त संख्या 17 के अनुसार रिपेयर का काम दो वर्षो में पूर्ण होना है। सितम्बर 2014 में हुए अनुबंध के दो वर्ष सितम्बर 2016

में पूरे हो जायेगें। इसके मुताबिक केवल पांच माह का समय शेष बचा है। अनुबन्ध के मुताबिक इसमें 15 करोड़ का तो सिविल वर्क ही होना है। लेकिन अभी तक मौके पर कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है इसमें बहुत सारी अनुमतियां प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला से आनी है। इन अनुमतियों की स्थिति इस समय क्या है इस पर अधिकारिक तौर पर कोई कुछ भी कहने से बच रहा है। ऐसे में पांच माह में 17.50 करोड़ का काम कैस पूरा होगा अपने में ही कई सवाल खड़े कर जाता है। इस चर्च की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई भी तकनीकी जानकार यह मानने को तैयार नही है कि इसकी रिपेयर पर 17.50 करोड़ रूपये खर्च हो सकते हैं क्योंकि यह पूरा भवन कहीं से भी लेश मात्र भी क्षतिग्रस्त नहीं है।

इस चर्च का जिर्णोद्वार भारत सरकार के माध्यम से एशियन विकास बैंक से लिये गये कर्ज से किया जा रहा है। यह चर्च शहर की हैरिटेज संपतियों में शामिल है। हरिटेज के तहत सारा निर्माण कार्य प्रदेश का पर्यटन विभाग करवा रहा है और इसके लिये यू एस क्लब में पर्यटन विभाग को अतिरिक्त कार्यालय की सुविधा दी गयी है। पर्यटन विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है और उनके प्रधान सचिव अतिरक्त मुख्य सचिव वी सी फारखा के पास विभाग सचिव की जिम्मेदारी है। पर्यटन विकास के लिये प्रदेश में अलग से एक बोर्ड गठित है जिसके उपाध्यक्ष पूर्व पर्यटन मन्त्री विजय सिह मनकोटिया हैं। पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष वीरभद्र के विश्वस्त हरीश जनारथा है। यह सभी लोग पर्यटन विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं। हैरिटेज संरक्षण के लिये हैरिटेज कमेटी भी गठित है। इस रिपेयर के लिये हस्ताक्षरित अनुबन्ध के अनुसार यह सारा काम हैरिटेज मानदण्डों के अनूरूप होना है। इस सबका अर्थ यह हो जाता है कि 17.50 करोड़ की रिपेयर का प्रारूप निश्चित तौर पर इन सबके हाथों से गुजरा है और इसके लिये सबकी अनुमति रही होगी। अब पांच माह में यह काम कैसे पूरा किया जाता है या इसमें समय और बढ़ाया जाता है यह तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन यह भी सवाल उठ रहा है कि 2014 में हस्ताक्षरित हुए अनुबन्ध पर अब तक कोई कारवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी ओर इस अनुबन्ध पर पर्यटन विभाग के साथ इण्डिया के कर्मचारियों/पदाधिकारियों की ओर से हस्ताक्षर किये गये हैं। स्मरणीय है कि चर्च आफ नार्थ इण्डिया का गठन छ: चर्च सूमहों को एक संस्था के तहत लाने के लिये किया गया था। लेकिन सी एन आई के गठन के बाद इसके सदस्यों/पदाधिकारियों पर चर्च एवम अन्य संपत्तियों के दुरूपयोग और उनको गलत ढंग से बेचने आदि के आरोप जब सामने आने लगे तब कुछ लोगों ने सीएनआई के गठन को यह कहकर अदालत में चुनौती दे दी की यह संस्था षडयंत्र करके इन संपत्तियों को हड़पने का प्रयास कर रही है। इसमें देश के कई हिस्सों में सी एन आई के लोगों पर बने आपराधिक मामलों में सजा तक भी हो चुकी है। इसी सबको सामने रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सी एन आई के गठन को ही अवैध करार देते हुए उसे ऐसी संपत्तियों से तुरन्त प्रभाव से बेदखल करके यह संपत्तियां उन मूल संस्थाओं को वापिस कर दी है जिनके पास यह 1948 में भारत सरकार के फैसले के बाद गई थी। क्योंकि अग्रेंजी शासन काल चर्च और अन्य संपत्तियों की देख रेख की जिम्मेदारी सरकार के पास थी। लेकिन 1948 में ही भारत सरकार ने हिन्दू धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों की तर्ज पर इनकी जिम्मेदारी भी स्थानीय संस्थाओं को सौंप दी थी। हिमाचल में भी ऐसी संपत्तियों को लेकर बड़ी विवादित स्थिति है। ऐसे में सी एन आई को लेकर आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी पर्यटन विभाग का सी एन आई के साथ अनुबन्ध साईन करना कई सवाल खडे करता है।

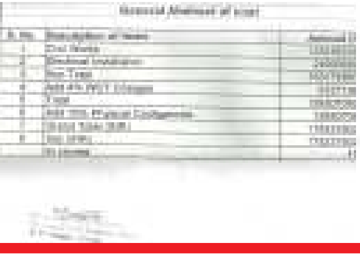

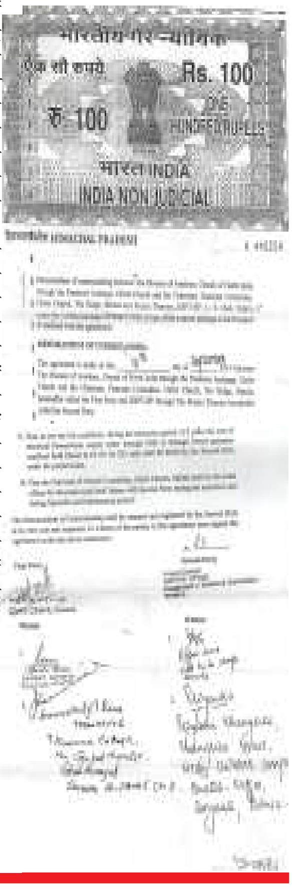
Rs. 100
रु 100
ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL